



2,000 रुपये के नोट होंगे चलन से बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुरुआत को घोषणा की। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में 23 मई से जमा या बदला जा सकता है।

आरबीआई ने शुरुआत शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। उसने बैंकों से 30 सितंबर तक ए नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में जाकर 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले एवं जमा किए जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। बहरहाल आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2,000 रुपये के नोट बैंकों में जमा या बदल सकता है। लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदलने का उल्लेख किया है। आरबीआई का यह कदम नवंबर, 2016 के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है जिसमें घोषणा की आधी रात से ही 500 एवं 1,000 रुपये के तत्कालीन नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। उसी समय आरबीआई ने पहली बार 2,000 रुपये के नोट जारी किए थे। केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऊंचे मूल्य वाले नोट का इस्तेमाल काला धन जमा करने में किए जाने संबंधी चिंताओं के बीच उठाया है। आरबीआई ने 2,000 रुपये के नए नोट छापना वित्त वर्ष 2018-19 में ही बंद कर दिया था और धीरे-धीरे उनका चलन काफी कम हो चुका है। इसी के साथ बैंकों के पास अन्य मूल्यों के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को नोट देने में कोई समस्या नहीं

... दो हजार रुपए का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा।



2018-19 में बंद कर दी थी प्रिंटिंग

दो हजार रुपये के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 14 (1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटों को लाया गया था। दो हजार रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था। इसलिए 1,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग 2018-19 में बंद कर दी गई थी।

होगी।

आरबीआई ने कहा, इसे ध्यान में रखने के साथ आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति के अनुरूप 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। आरबीआई दो हजार के नए नोट जारी नहीं करेगा। हालांकि, ये बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है। रिजर्व

बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी की है। आपको बता दें कि साल 2016 में पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में आए थे। 2,000 रुपये के नोट के लिए आरबीआई ने कहा है कि अब 2,000 रुपये के बैंक नोट बंद हो गए हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। आप इन नोटों को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने शुरुआत को रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है।

आरबीआई ने कहा है कि अब 2,000 रुपये के बैंक नोट (2,000 Rupee Note) बंद हो गए हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं, तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं।

आरबीआई के फैसले की मुख्य बातें

- ▶ लोग दो हजार रुपए के नोट को बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उसे बैंकों एवं आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं।
- ▶ दो हजार का नोट बैंक खातों में बिना किसी बाधा के जमा किए जा सकते हैं। हालांकि यह अपने ग्राहक को जानों (केवाईसी) मानकों का पूरा करने पर निर्भर है।
- ▶ लोग 23 मई से एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य तक के दो हजार रुपए के नोट बदल सकते हैं।
- ▶ बैंक प्रतिनिधियों के जरिए बैंक खाताधारक 4,000 रुपए मूल्य तक के दो हजार रुपए के नोट बदल सकते हैं।
- ▶ नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपए का नोट जारी किया गया था।
- ▶ नवंबर 2016 में नोटबंदी के उलट 2,000 रुपए का नोट 30 सितंबर वैध मुद्रा बना रहेगा।
- ▶ यह कहा जा रहा था कि दो हजार रुपए के नोट का उपयोग कथित रूप से काला धन जमा करने और काले धन को सफेद बनाने में किया जा रहा था। इसको देखते हुए दो हजार रुपए के नोट को चलन से हटाने का फैसला किया गया।
- ▶ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2,000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी।
- ▶ दो हजार रुपए के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे।
- ▶ मार्च 2018 में चलन में मौजूद कुल नोट में दो हजार रुपए के नोट की हिस्सेदारी 37.3 प्रतिशत थी जो 31 मार्च, 2023 को घटकर 10.8 प्रतिशत रह गई। मूल्य के हिसाब से मार्च 2018 में कुल 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट 2,000 रुपए के थे जबकि 31 मार्च, 2023 को इनका मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया।

आरबीआई ने शुरुआत को एक रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये का नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है।

लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। 2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था।

नोटबंदी का जिन्न फिर बाहर आया: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शुरुआत को सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटबंदी वाला जिन्न फिर से लोगों को परेशान करने के लिए बाहर आ गया है तथा सरकार को ऐसे कदम के मकसद के बारे में बताना चाहिए। मुख्यमंत्री विपक्षी दल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार अपना जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडा जारी रखे हुए है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, स्वयंभू विश्वगुरु की चिरपरिचित शैली। पहले करो, फिर सोचो। आठ नवंबर, 2016 को तुंगलकी फरमान (नोटबंदी) के बाद बड़े धूमधाम से 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। अब इसे वापस लिया जा रहा है।

1000 रुपए का नोट फिर से जारी हो जाए: चिदंबरम

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शुरुआत को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हैरानी नहीं होगी कि यदि 1000 रुपए का नोट फिर से जारी हो जाए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, जैसी संभावना थी उसी के मुताबिक सरकार आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला किया। 1000 रुपए का नोट लेनदेन के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। हमने यह नवंबर, 2016 में कहा था और अब सही साबित हुए हैं। उनका कहना था, 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के पूर्वतापूर्ण फैसले को ढंकने के लिए 2000 रुपए का नोट बैंड-एड की तरह था।

एवरेस्ट के रास्ते में महिला की मौत, पेसमेकर के साथ फतह करना चाहती थीं माउंट एवरेस्ट

काठमांडू। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के बेसकैम्प में बीमार पडने के बाद 59 वर्षीय एक भारतीय पर्वतारोही की मौत हो गई, जो दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली एशिया की पेसमेकर वाली पहली महिला बनने का विश्व रिकार्ड कायम करना चाहती थीं। नेपाल के पर्यटन विभाग के निदेशक युवराज खातिवादा ने बताया कि महाराष्ट्र की रहने वाली 59 साल की सुजान्ने लियोपोल्डिना जीसस को बेस कैम्प से महज 250 मीटर की चढ़ाई करने में 12 घंटे का समय लगा। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसने लुकला के हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया।



रफ्तार नहीं बनाए रख पाने तथा चढ़ने में

परेशानी होने पर सुजान्ने को माउंट एवरेस्ट फतह करने की कोशिश छोड़ देने को कहा गया था।

सुजान्ने को पेसमेकर लगा था। निदेशक ने बताया कि सुजान्ने ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ेगी ही, क्योंकि वह इस चोटी पर चढ़ने की अनुमति पाने के लिए पहले ही शुल्क दे चुकी हैं। बता दें कि पिछले तीन दिनों में यह चौथी मौत की घटना है। मार्च से शुरू हुए मौजूदा सीजन के दौरान अब तक माउंट एवरेस्ट पर आठ चीनी और भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। रिपोट्स के मुताबिक फिलहाल 175 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं।

आवश्यक सूचना

'उत्तराखण्ड प्रहरी' के सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रिय अखबार 'उत्तराखण्ड प्रहरी' महाभियान में शामिल हो सकते हैं। आप अपने द्वारा लिखी गई कोई भी संरचना, कविता, कहानी, लेख या कार्यक्रम हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छे लेख व कहानी को 'उत्तराखण्ड प्रहरी' में उचित स्थान दिया जाएगा। आप अपने प्रियजनों को जन्मदिन, सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर बधाई संदेश भी दे सकते हैं।

आप हमें ईमेल

uttarakhandprahari19@gmail.com या
whatsapp no 8077771906 पर भी भेज सकते हैं।

संपादकीय

'कर्जमुक्त भारत' अभियान

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 24 मई को ऐसा अनशन, धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी मांगें राजनीतिक, धार्मिक, किसानी, यौन-शोषण, आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी हुईं नहीं हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और देश को कर्जमुक्त करने का अभियान है। सरकारें और राजनीतिक दल कर्जमाफी को जुमले के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। सिर्फ किसानों के कर्ज माफ करने के वायदे, बार-बार, किए जाते रहे हैं और कर्ज माफ भी किए गए हैं, लेकिन यह आयाम अनदेखा और उपेक्षित रहा है कि कर्ज के कारण लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। बीते वर्ष 2022 में ही 20,000 से अधिक कर्जदार लोगों ने आत्महत्याएं कीं। 'धार्मिक एकता ट्रस्ट' के प्रतिनिधियों ने नायाब कोशिशों की हैं। वे न केवल कर्जमुक्त होने के प्रशिक्षण दे रहे हैं, बल्कि रास्ता भी सुझा रहे हैं। इस अभियान के तहत 3 लाख भारतीय जुड़े हैं। पूरा डाटा सार्वजनिक है। वे 'कर्जमुक्त भारत' का अभियान देश भर में छेड़े हैं। बेशक जंतर-मंतर का अनशन एकदिनी और प्रतीकात्मक होगा, लेकिन वे देश के सामने कुछ तथ्य और सत्य पेश करना चाहते हैं। ट्रस्ट के प्रतिनिधि और संस्थापक शाहनवाज चौधरी दो बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर के अधिकारियों को भी अपनी बात बताई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में 7 मुलाकातें शीर्ष के अधिकारियों से हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सामने भी अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन सरकार और अफसरशाही देश के सरोकारी और मानवतावादी नागरिकों की सलाह मानने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का आग्रह है कि जिनकी मौत हो चुकी है या जो लोग कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हैं, सरकार उनका 10 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करे अथवा 'राइट ऑफ' कर दे। तुलना अडाणी केस से की गई है। हम उसे गलत मानते हैं।

उद्योगपतियों, किसानों और आम नागरिकों के कर्ज अलग-अलग किस्म के होते हैं, लिहाजा सरकार उसी संदर्भ में कर्जों को माफ करती रही है। यदि सरकारें वोट पाने की खातिर 'मुफ्त की रेवडियां' बांट सकती हैं या कर्ज माफ कर सकती हैं, तो देश के अक्षम नागरिकों की मदद करने में क्या गुरेज है? ट्रस्ट से जुड़े और पेशेवर चिकित्सक डॉ. खरबंदा से हमने बातचीत की, तो उन्होंने इसे सर्वधर्मवादी और मानवतावादी अभियान करार दिया। उनका विश्लेषण है कि इतने नागरिकों का कर्ज माफ करने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। सरकार जिनके 5-6 लाख करोड़ रुपए माफ करती है या बैंकों के पैसे मार कर जो उद्योगपति 'भगोडा' बन जाते हैं, उनके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था अनवरत गति से विकसित हो रही है। डॉ. खरबंदा के मुताबिक, सांसदों को भी पत्र लिखे जा चुके हैं। लोग नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना और लॉकडाउन से आज भी त्रस्त और प्रभावित हैं। देश के हुक्मरानों को इस संवेदनशील मुद्दे पर जागृत होकर कुछ करना चाहिए। बहरहाल भारत की अर्थव्यवस्था करीब 325 लाख करोड़ रुपए की है, जो निरंतर बढ़ रही है। यह कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है। हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी भारतीय गरीबी-रेखा के तले जी रहे हैं या आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह देश की प्रतिष्ठा और नीतियों को ही खंडित करने वाली स्थिति है। यह कोई सांप्रदायिक या आरक्षणवादी अभियान भी नहीं है। सरकार लोगों के कर्ज को वर्गीकृत कर माफ कर सकती है। दुर्घटनाएं होती हैं, त्रासदियां भी घटती हैं, आपदाएं आती हैं, सरकार प्रत्येक जनवादी स्थिति में लोगों की आर्थिक मदद करती है।

मधुमक्खी एक, फायदे अनेक

मधुमक्खियां नर फूलों से परागण एकत्रित कर जब मादा फूल पर भ्रमण करती हैं तो उनके शरीर से चिपके परागकण फूल के मादा भाग के संपर्क में आकर परागण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इनसान के बेबुनियादी हस्तक्षेप के कारण आज मधुमक्खियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है, जिससे इनकी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। हाल के दशकों में मौसम परिवर्तन व कृषि में रसायनों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मधुमक्खियों की आबादी विश्व स्तर पर कम होती जा रही है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा 'मीठी क्रांति' के नाम से एक पहल की गई जिसके अंतर्गत वर्ष 2021-23 तक 500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया

पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि क्षेत्र में मधुमक्खियों की भूमिका को नकार पाना नामुमकिन है। मधुमक्खियों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 'यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं तो मानव जाति मात्र चार वर्षों तक ही जीवित रह पाएगी।' मधुमक्खियों के महत्व तथा सतत विकास में इनके योगदान को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2017 में प्रति वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 20 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह वो दिन था जिस दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा (1734-1773) का जन्म हुआ था। जानसा स्लोवेनिया में मधुमक्खी पालकों के एक परिवार से संबंध रखते थे। यह परिवार पारंपरिक तरीके से मधुमक्खियों का रखरखाव करता था। लेकिन जानसा द्वारा आधुनिक मौनपालन की विधि को अपनाया

गया जिसके चलते उन्हें स्कूल में मौनपालन शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2018 में पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 में इस दिवस को 'बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर-फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन' विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है। मधुमक्खियां परागणकर्ता के रूप में

विश्व भर में लगभग 18.8 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जाता है, जबकि भारत में 1.08 लाख मीट्रिक टन शहद उत्पादित किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत से 61333 मीट्रिक टन शहद निर्यात किया गया जिसकी कुल कीमत 1489.81 करोड़ रुपए थी। औषधीय गुणों से

भरपूर शहद का आयुर्वेद में विशिष्ट स्थान रहा है। इसे लगभग 600 प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि आयुर्वेद के जनक भारत देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 50 ग्राम शहद का उपभोग किया जाता है, जबकि विश्व में यह 250 से 300 ग्राम है। सबसे अधिक जर्मनी में यह प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम प्रति वर्ष है।

मधुमक्खी से हमें शहद के अलावा अन्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें रॉयल जैली, पोलन, मोम, प्रोपोलिस व जहर शामिल हैं। मधुमक्खी के विष को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कीमत बाजार में एक करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। गठिया, कैंसर, पार्किंसन, अल्जेमर आदि रोगों के उपचार हेतु इसे प्रभावशाली माना गया है। रॉयल जैली, प्रोपोलिस और मोम का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन व औषधि उद्योग में किया जाता है। इन उत्पादों के अतिरिक्त मौन पालक मक्खियों को प्रजनन के माध्यम से नई रानी तैयार करके अथवा मौन वंशों को विभाजित कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हिमाचल के सेब बहुल क्षेत्रों में फूलों के खिलने के समय परागण के उद्देश्य से मधुमक्खियों के डिब्बों को बागीचे में रखा जाता है। मौन पालक इन डिब्बों को किराए पर देते हैं, जिससे बागीचों की फल उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है।



दुनिया के 35 प्रतिशत फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं तथा दुनिया भर की 87 प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करती हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिककी) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मधुमक्खियों द्वारा की गई सेवाओं की कीमत प्रति वर्ष 15000 से 20000 करोड़ रुपए आंकी गई है। कृषि व बागवानी के क्षेत्र में किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में मधुमक्खियों का अहम योगदान रहता है। विश्व भर में मधुमक्खियों की लगभग 20000 प्रजातियां पाई जाती हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से किसान अच्छी आय अर्जित कर रहा है। यह एक वैश्विक गतिविधि है, जिससे लाखों मधुमक्खी पालक अपनी आजीविका के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं।

उत्तराखण्ड प्रहरी

कविता

दोस्त ऐसा हो....



रास्ता ऐसा हो जो मंजिल तक ले जाए।
धन इतना हो कि गुजर बसर हो जाए।।
खानपान ऐसा हो कि आत्मा तृप्त हो जाए।
शिक्षक ऐसा हो जो ज्ञान का भंडार भर जाए।।
ज्ञान ऐसा हो कि जीवन संवर जाए।
शब्द ऐसे हो जो दिल को छू जाए।।
वाणी ऐसी हो जो मधुर रस घोल जाए।
संगीत ऐसा हो कि तन मन झूम जाए।।
दोस्त ऐसे हो 'बेदी' जो हर काम में सहयोग दे जाए।
जीवन साथी ऐसा हो जो हर कदम पर साथ निभाता जाए।।
नेता ऐसा हो जो हर वादा निभा जाए।
अपनापन ऐसा हो कि एहसास हो जाए।।



सचिन बेदी अधिवक्ता, हरिद्वार

कभी अपनी गिरेबां में क्यों नहीं झांकते 'श्रीमान'!



निशिकांत ठाकुर

चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन चुनाव में कही गई बातें मिट्टी में दफन हो जाती हैं। चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी वादे किए जाते हैं या जनता को सब्जबाग दिखाए जाते हैं, राजनीतिज्ञों द्वारा सबके सब अगले चुनाव के लिए नमक—मिर्च लगाकर रख लिया जाता है। जनता तो भूल जाती है कि कितने मधुर दिवास्वप्न उसे दिखाए गए थे। चुनाव के बाद के लिए उसने कितने हसीन स्वप्न देखे थे, लेकिन यह क्या? सच में सब जुमले ही साबित हुए। चुनी गई सरकार के मंत्री शायद आचार्य

कणिक के इस सिद्धांत को अपनाते हैं, जो ज्ञान उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया था। आचार्य कणिक (धृतराष्ट्र के कूटनीतिक मंत्री) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिनके द्वारा राज्य छीने जाने का कोई भी संकट हो, उन्हें निश्चित रूप से शत्रु समझा जाए और ऐसे लोगों को कभी भी जीवित नहीं छोड़ा जाए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह यह भी कहते हैं कि चतुर राजा वही है, जो देने की बात तो करे, लेकिन दे नहीं। जितना संभव हो, टालता रहे। आचार्य कणिक की मंत्रणा थी कि पांडवों को राज्य देने की बात तो की जाए, किंतु उन्हें दिया न जाए तथा जितनी जल्दी संभव हो, पांडवों का वध कर दिया जाए। अक्षरशः सत्य, इसी तरह आज के कुछ राजनीतिक दल के नेता शायद आचार्य कणिक की धृतराष्ट्र को दिए गए इस मंत्रणा को आत्मसात करके सत्ता में आते ही उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं।

यह ठीक है कि सरकार जनता को अपनी उपलब्धियां खूब महिमामंडित

करके बताए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं पर भी राजनीतिक रोटियां संकने लगे तो इसे क्या कहा जा सकता है। पुलवामा में जवानों की शहादत को वोट बैंक में तब्दील करना कोई भारत के राजनीतिज्ञों से सीख सकता है। भारत के लिए केंद्र में मजबूत सरकार को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में वोट मांगते हुए युवाओं से कहा कि बालाकोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भारत द्वारा हवाई हमले से आतंकीयों में डर पैदा हो गया है और पाकिस्तान में सत्तारूढ़ लोगों को बुरे सपने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा और कहा कि हवाई हमलों के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, लेकिन स्थानीय दोनों पार्टियां दुखी थीं। स्पष्ट रूप से उनका इशारा डॉ. फारुख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती परिवार के लिए था। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं

का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अपना पहला वोट उन बहादुर जवानों को समर्पित कर सकते हैं, जिन्होंने देश के लिए जान गंवा दी। आप गरीबों को घर दिलाने के लिए, गरीबों को मुफ्त इलाज दिलाने के लिए, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए वोट दे सकते हैं, तो उनका आशय साफ था कि शहादत पाए सैनिकों के लिए क्यों नहीं? उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में लोगों को केवल सांसद या प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार चुननी है। देश के फायदे के लिए केवल मजबूत सरकार कड़े फैसले ले सकती है। मोदी ने कहा था कि पांच वर्ष पहले ऐसा वक्त था, जब पाकिस्तान के आतंकी हम पर हमला करते थे और पाकिस्तान हमें धमकता था। हमारे बहादुर जवान कार्रवाई के लिए अनुमति मांगते थे, लेकिन सरकार तब डरी रहती थी। पता नहीं किस मजबूत सरकार के लिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे?

वैज्ञानिक सूचना

उत्तराखण्ड प्रहरी के संपादन में हम प्रयासरत हैं कि हमारी ओर से खबर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। हमारी कोशिश है कि अखबार में छपी किसी खबर, रिपोर्ट, फीचर या लेख से व्यक्ति विशेष, संगठन या समुदाय की भावना को ठोस न पहुंचे। उत्तराखण्ड प्रहरी में प्रकाशित लेख, विश्लेषण और साधारण, ली गई सामग्री के विचार संबंधित लेखकों और रचनाकारों के निजी विचार हैं, न कि अखबार के। अतः सभी पाठकों से आग्रह है कि वे किसी सूचना, समाचार, विज्ञापनों आदि के आधार पर कोई फैसला करने से पहले तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। उसके लिए किसी भी प्रकार से लेखक, संपादक, प्रकाशक, प्रिंटर या विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथा किसी भी कारोबारी और निज निर्णय के लिए उत्तराखण्ड प्रहरी जिम्मेवार नहीं होगा।

पत्रकारों को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति गोल्डन कार्ड की सुविधा मुहैया करवाई जाए

सुमित तिवारी / उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में उत्तरांचल प्रेस क्लब की अर्द्धवार्षिक स्मारिका/डायरेक्ट्री का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राज्य में पत्रकारों के लिए बीमा योजना शुरू करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में वहां की नियमावली का अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को प्रेस क्लब भवन निर्माण संबंधी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने और राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे पत्रकारों का चिहनीकरण करते हुए उन्हें स्थायी मान्यता प्रदान करने संबंधी पूर्व घोषणा के क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए।

प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा और महामंत्री विकास गुसाई ने पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त

सीएम धामी ने उत्तराखंड प्रेस क्लब की अर्द्धवार्षिक स्मारिका/डायरेक्ट्री का विमोचन किया



किया। क्लब कार्यकारिणी ने हाल ही आंदोलनकारी नेत्री सुशीला बलूनी के देहावसान पर सरकार की ओर दिए गए राजकीय सम्मान की पहल, गांवों में मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम और घोषणाओं पर अमल के लिए शीघ्र शासनादेश जारी करने जैसी पहल को लेकर भी मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह

के कदमों से आमजन के बीच सकारात्मक संदेश जा रहा है। महामंत्री विकास गुसाई ने पत्रकारों को अटल आयुष्मान योजना में पत्रकारों को भी कर्मचारियों की भांति गोल्डन कार्ड की सुविधा मुहैया कराने का आग्रह किया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल ने मुख्यमंत्री का ध्यान मध्य

प्रदेश सरकार की ओर से पत्रकारों के लिए चलाई जा रही 20 लाख रुपये की बीमा योजना की ओर दिलाते हुए आग्रह किया कि उत्तराखंड में भी सरकार को पत्रकारों के लिए अंशदान आधारित इसी तरह की बीमा योजना आरंभ करनी चाहिए। क्लब अध्यक्ष राणा और पूर्व अध्यक्ष अंथवाल ने क्लब भवन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण जल्द कराए जाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे पत्रकारों को स्थाई मान्यता संबंधी पूर्व घोषणा की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया। इस मौके पर क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मि खत्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष दरबान सिंह, संयुक्त मंत्री राजीव थपलियाल व मीना नेगी, कोषाध्यक्ष मनीष चंद्र भट्ट, कार्यकारिणी सदस्य दयाशंकर पांडे, फहीम तन्हा, मंगेश कुमार, राम अनुज, बीपी कुकरेती, सुबोध भट्ट आदि मौजूद रहे।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने संमाला कार्यभार

हरिद्वार। शुक्रवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) अभिनव त्यागी ने हरिद्वार स्थित अग्निशमन कार्यालय में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान सीएफओ अभिनव त्यागी ने कहा कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को अग्नि से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम चलाकर लोगों को अग्नि से बचाव के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने



कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों-कर्मचारियों से जानकारी हासिल की। सीएफओ अभिनव त्यागी ने निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के सभी होटल एवं फैक्ट्री संचालक एवं प्रबंधक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानक के अनुसार तत्काल अधिष्ठापित करा लें। बिना अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था के संचालन कदापि न करें। यदि फैक्ट्री या होटल में अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था संसाधनों का अधिष्ठापन नहीं किया जाता है तो जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि होटल और फैक्ट्रियों एवं अन्य सभी प्रतिष्ठानों पर अग्नि सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जाएगा। संचालक और कर्मचारियों को अग्नि से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजों में भी अग्नि सुरक्षा बचाव संबंधी जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विधानसभा भर्ती प्रकरण

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका खारिज कर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर लगाई

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

नैनीताल (देहरादून)। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के विशेष याचिका को निरस्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है।

उत्तराखण्ड विधानसभा में नियमों के विरोध तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में आज उच्चतम न्यायालय ने पुनः उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराते हुए बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा दाखिल याचिका (SLP) को मात्र डेढ़ मिनट की सुनवाई में निरस्त कर दिया। उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय की ओर से पैरवी कर रहे वकील अमित तिवारी ने बताया कि वर्ष 2021 में विधानसभा में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका (एसएलपी) को आज उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच के न्यायधीश हृषिकेश राय और न्यायधीश मनोज मिश्रा द्वारा सुना गया जिसमें डबल बेंच ने मात्र डेढ़ मिनट में ही याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया और उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराया। आपको बता दे की



विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। जिसमें 2016 से 2021 में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की विशेषज्ञ जांच कमेटी की

रिपोर्ट के आधार पर सेवाएं समाप्त की गई। भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्तियां नियम व पारदर्शिता हो इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन की पहल की थी। उत्तराखण्ड विधानसभा अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरेगी।

इस संशोधन के साथ शासन ने सेवा नियमावली पर सहमति जताते हुए इसे विधानसभा को लौटा दिया है। संशोधित नियमावली में विधायी को फिर से विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय में विधानसभा सचिवालय उत्तराखण्ड की ओर से वकील अमित तिवारी और वकील अर्जुन गर्ग ने पैरवी की।

जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाया और लाखों का चालान वसूला

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून 19 मई 2023 जिलाधिकारी सोनिका ने दून विश्वविद्यालय रोड आदि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम को जनमानस के लिए सुगम सुविधा मुहैया कराने के दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अंशपालन में टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। दून यूनिवर्सिटी के समीप टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग धनराशि ₹0 56000 का अर्थदण्ड लगाया गया, जिसमें नगर निगम देहरादून द्वारा कुल 33 चालान करते हुए लगभग धनराशि ₹0 29500 अर्थदण्ड की कार्यवाही तथा पुलिस टीम द्वारा धनराशि ₹0 4000 तथा संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 21 चालान करते हुए लगभग धनराशि ₹0 22500 के अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी।

जनपद में अतिक्रमण से बाधित सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए हैं, जिनके लिए नगर निगम, पुलिस, प्रशासन की अलग-अलग



संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। आज घंटाघर से सहारनपुर चैक, महिन्द्रा शोरूम हरिद्वार रोड से दून यूनिवर्सिटी तक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से आईटी पार्क वाया परेडग्राउण्ड, घंटाघर से बल्लुपुर, घंटाघर से मसूरी डाईवर्जन आदि स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।

टीमों द्वारा आज अपने-अपने जोन में 35 स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने की

कार्यवाही की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा कुल 98 चालान करते हुए लगभग धनराशि ₹0 81300 अर्थदण्ड की कार्यवाही तथा पुलिस टीम द्वारा 35 चालान करते हुए लगभग धनराशि ₹0 17500 के तथा संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 53 चालान करते हुए लगभग धनराशि ₹0 62300 के अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी। टीम द्वारा चेतावनी दी गई है कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाए अन्यथा भारी अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ ही सामग्री जब्त कर ली जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की नियमित प्रक्रिया चल रही है, कई स्थानों पर लोग सामान फुटपाथ पर रख दे रहे हैं, उन्होंने जनमानस से अनुरोध किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु जो अभियान चल रहा है उसमें सहयोग करें ताकि फुटपाथ खाली रह सके। कहा अतिक्रमण मुक्त किये गए स्थानों पर दुबारा अतिक्रमण किये जाने पर अभी तो अर्थदण्ड लग रहा, बार-2 ऐसा किये जाने पर विधिक कार्यवाही अमल लाई जाएगी। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें। इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें।

हरिद्वार में मुद्रित दामों से अधिक दामों में बेची जा रही है दुकानों पर शराब

हरिद्वार। पथरी रेलवे फाटक के निकट अंग्रेजी शराब की दुकान का है जब शाम के समय एक जागरूक ग्राहक शराब की दुकान पर पहुंचा तो उसने बीयर की एक बोतल खरीदी जिस पर मुद्रित मूल्य ₹185 लिखा था और ग्राहक से ₹200 लिए गए जब इस संबंध में ग्राहक द्वारा विरोध किया गया तो दुकान पर मौजूद सेल्समैन बिजेन्द्र सिंह रावत द्वारा पुराना स्टॉक होने की बात कही गई। जब ग्राहक के अपनी संतुष्टि के लिए दुकान के बाहर आबकारी विभाग के फोन नंबर पर संपर्क करना चाहा तो वहा आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारी का फोन नंबर नहीं लिखा पाया गया। वही दूसरा मामला गांव सहदेवपुर देसी मंदिरा की दुकान का है। जहां ग्राहक से बीयर की बोतल पर मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य लिए गए। ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि जनता की मेहनत की कमाई को शराब ठेकेदारों द्वारा ओवर रेंटिंग के जरिए लूटने का धंधा चलता रहेगा। या इन पर कोई उचित कार्रवाई होगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की सूचना विभाग को कई बार पहले भी मिली है जिसमें उचित कार्रवाई की गई है। और आगे भी इस तरह की शराब की दुकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी।



पर्यटन योजनायें बने रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं। नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लोग कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका पूरा आंकलन किया जाए। जिन योजनाओं में आम जन का रूझान बढ़ा है, इनमें यदि टॉपअप लोन अथवा सब्सिडी की धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, तो इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखण्ड@25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किये गये अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ राज्य के सभी पात्र लोगों को मिले, इसके लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए, जिससे यह पता चले सके कि कौन सा परिवार किन योजनाओं का लाभ लेने का पात्र है, और कितने परिवार योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो जरूरतमंद लोग सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी

राज्य की प्रमुख घाटियों की भी की जाय पर्यटन की दृष्टि से ब्रांडिंग



योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको विभिन्न संचार एवं प्रचार माध्यमों से योजनाओं की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होम स्टे को और बढ़ावा देने की जरूरत है। होम स्टे को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिकी को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से भी अपील की है, कि अपने जनपद भ्रमण के दौरान होम स्टे में जरूर रुकें, इससे इनको और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि होम स्टे चलाने वालों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अगले 10

सालों का विभागों द्वारा जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है, उसमें भविष्य की सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रोडमैप पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाएं। 2025 तक जिन कार्यों एवं योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनमें अभी से कार्य धरातल पर दिखने शुरू हो जाए। उन्होंने 2030 तक के पूरे रोडमैप पर सुनियोजित तरीके से कार्य किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन आधारित जो भी नई गतिविधियां की जा रही हैं और जिन स्थानों पर की जा रही हैं, पर्यटन विभाग द्वारा उनका वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में विभागों

को आपसी समन्वय के साथ तेजी से आगे बढ़ना होगा। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भी यह जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शीघ्र ही पर्यटन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक की जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के चिन्हित वाइब्रेट विलेज के आस-पास भी पर्यटन गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। पर्यटक स्थलों के आस-पास हेलीपैड की भी व्यवस्थाएं रखी जाएं। मानसखण्ड मन्दिर परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों दिये। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रथम चरण में जिन 16 मन्दिरों को चिन्हित किया गया है, उन पर मिशन मोड में कार्य किये जाएं। विभिन्न पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों पर जिन पौराणिक गुफाओं को विकसित किये जाने की योजना है उन पर भी तेजी से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें राज्य की प्रमुख वैलियों की पर्यटन की दृष्टि से ब्रांडिंग करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में स्थित घाटियों के महत्व एवं प्राकृतिक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाए। पर्यटन मंत्री सताल महाराज ने कहा कि राज्य में ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इस दिशा में

तेजी से कार्य भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन डेस्टिनेशन के क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड @ 25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किये गये अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में मातृत्व मृत्युदर को और कम करने के लिए प्रयास किये जाएं। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन खुशियों की संवारी का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को लंबी लाइन पर खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। ई-संजीवनी एप का वृहद स्तर पर प्रचार किया जाए। जिससे अधिकांश लोग घर से ही चिकित्सकों से परामर्श ले सकें। उन्होंने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागों द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं, इसकी भी समीक्षा की जायेगी।

देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपद से हुई सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति



उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में राजस्व अर्जन और संसाधन वृद्धि की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा की जा रही आनलाईन रजिस्ट्री, विभागीय कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी के प्रयोग, डिजिटाइजेशन की प्रगति तथा राजस्व वृद्धि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंत्री ने गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक राजस्व की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपद में विभाग को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्ति हुई है तथा अन्य जनपदों में भी उन्होंने राजस्व वृद्धि हेतु आवश्यक निर्देश दिये।

मंत्री ने सभी राजकीय विभाग जिनमें स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है, इन विभागों से राजस्व प्राप्ति हेतु अधिकारियों से चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में

विभागीय अधिकारियों ने मा. मंत्री को अवगत कराया कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के लगभग सभी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में आने वाले आवेदकों के लिए आवश्यकतानुसार टिन शेड एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा कार्यालयों को कैशलेस करना, वर्चुअल पंजीकरण प्रणाली को लागू करना, पुराने अभिलेख का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन करना, आधार प्रमाणीकरण/ई-के.वाई.सी. तथा ब्लॉकचेन डी.एम.एस. और क्यू.आर. कोड सत्यापन आदि कार्ययोजनाओं को जनहित में प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे आमजन को पारदर्शी और सुविधाजनक कार्यप्रणाली उपलब्ध करायी जा सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन, महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, डॉ. अहमद इकबाल एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

यदि आरोपों की पुष्टि हुई तो कांग्रेस करेगी उचित कार्रवाई : करन महारा

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। देहरादून के कप्तान द्वारा प्रेस वार्ता कर कुछ लोगों को जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी बताया गया है। उपरोक्त प्रकरण में कांग्रेस के एक नेता का नाम भी चर्चाओं में है। इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखण्ड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन महारा ने कहा है। कि पार्टी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है यदि जांच सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से संगठन अपने पदाधिकारी पर उचित कार्यवाही करने से गुरेज नहीं करेगा। परंतु यदि आरोप सही नहीं पाए गए तो निश्चित रूप से छवि धूमिल



करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से जवाब मांगा जाएगा। महारा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के जैसी नहीं है कि सरेआम सड़कों पर मारपीट करने वाले मंत्री के खिलाफ

पुख्ता साक्ष्य और प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद संगठनात्मक रूप से कोई कार्यवाही ना करें। कांग्रेस एक अनुशासित एवं पारदर्शी संगठन है। महारा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा नहीं है कि देश को गौरवान्वित करने वाली और गोल्ड मेडल लाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय व अत्याचार करने वाले सांसद को बचाने के लिए लीपापोती करें। महारा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड कांग्रेस के पदाधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी तो बिना समय गंवाए हुए पार्टी अनुशासनात्मक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

सोनिया बस्ती में शुरू हुआ सड़क निर्माण, विधायक और पार्षदों ने नारियल फोड़कर किया कार्य का शुभारंभ

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। हरिद्वार वार्ड 42 स्थित सोनिया बस्ती में सड़क निर्माण कार्य का विधायक, पार्षद और मेयर प्रतिनिधि ने स्थानीय निवासियों के साथ नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा जनता के कार्य करने चाहिए। जनता विकास कार्यों के लिए विधायक, मेयर, पार्षद, सांसद आदि का चुनाव करती है। कांग्रेस सदैव विकास कार्यों के पक्ष में रही है। पार्षद दीपिका बहादुर ने कहा कि मेयर अनिता शर्मा के सहयोग से वार्ड में विकास कार्य प्रगति पर हैं। बीजेपी सरकार होने के कारण विकास कार्यों में देरी हुई लेकिन फिर भी वार्ड की कॉलोनियों में सड़क, नाली,



सीवर, पथ प्रकाश आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने कहा कि मेयर प्रत्येक वार्ड में कार्य करवा रही है। इसके साथ ही नगर निगम की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे भी मेयर द्वारा हटवाए जा रहे हैं। किसी को भी अवैध कब्जे करने नहीं

दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री नईम कुरेशी, मकबूल कुरेशी, पार्षद सोहेल कुरेशी, शहजाद फाइट्टर, सुनील कुमार, सतेंद्र वशिष्ठ, शाईदा कुरेशी, वसीम कुरेशी, सुजात कुरेशी, जुल्नू कुरेशी, आबाद, मयंक सिंह आदि उपस्थित थे।

aws भारत में करेगा 12.7 अरब डॉलर का निवेश

मुंबई। एमेज़ॉन वेब सर्विसेज़ ने भारत में 2030 तक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में 12.7 अरब डॉलर अर्थात 1,05,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की आज घोषणा की। कंपनी ने यहां कहा कि यह निवेश भारत में ग्राहकों द्वारा क्लाउड सर्विसेज़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस निवेश से 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1,94,700 करोड़ रुपये (23.3 अरब डॉलर) का योगदान मिलेगा। भारत में डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस योजनाबद्ध निवेश से हर साल भारतीय व्यवसायों में औसतन 1,31,700 फुलटाईम ईक्विवैलेंट (एफटीई) नौकरियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी। ये नौकरियाँ भारत में डेटा सेंटर सप्लाय चेन के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, एवं अन्य क्षेत्रों में होंगी।

इस नए निवेश की घोषणा से पहले एडब्ल्यूएस 2016 से 2022 के बीच 30,900 करोड़ रुपये (3.7 अरब डॉलर) का निवेश कर चुका है, जिसके बाद भारत में 2030 तक एडब्ल्यूएस का कुल निवेश बढ़कर 1,36,500 करोड़ रुपये (16.4 अरब डॉलर) हो जाएगा। भारत में एडब्ल्यूएस के निवेश का इन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर रिपल इफेक्ट पड़ेगा तथा कार्यबल के विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन के अवसरों, सामुदायिक संलग्नता और सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रमों का विकास होगा। ज्यादा जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

एडब्ल्यूएस के पास भारत में दो डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं - एडब्ल्यूएस एशिया पैसिफिक (मुंबई) क्षेत्र, जो 2016 में लॉन्च किया गया था और एडब्ल्यूएस एशिया पैसिफिक (हैदराबाद) क्षेत्र, जो नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ये दोनों एडब्ल्यूएस क्षेत्र भारतीय ग्राहकों को ज्यादा लचीलेपन और उपलब्धता के साथ वर्कलोड चलाने, भारत में डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर करने के विभिन्न विकल्प प्रदान करने और अंतिम यूजर को कम



लेटेसी के साथ सेवाएं देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एडब्ल्यूएस साल 2016 से 2022 के बीच एडब्ल्यूएस एशिया पैसिफिक (मुंबई) क्षेत्र में 30,900 करोड़ रुपये (3.7 अरब डॉलर) से ज्यादा निवेश कर चुका है। इसमें पूंजी और संचालन, दोनों तरह के खर्च शामिल हैं, जो कंस्ट्रक्शन, रखरखाव, और उस क्षेत्र में डेटा सेंटर चलाने से जुड़े खर्च हैं। एडब्ल्यूएस का अनुमान है कि 2016 से 2022 के बीच भारत की जीडीपी में इसके द्वारा 38,200 करोड़ रुपये (4.6 अरब डॉलर) से ज्यादा का योगदान दिया गया, और इस निवेश से भारतीय व्यवसायों में प्रतिवर्ष 39,500 एफटीई नौकरियों में मदद मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया विज़न भारत में क्लाउड और डेटा सेंटरों का विस्तार कर रहा है। भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवेश में इंडिया क्लाउड और बुनियादी डेटा सेंटर का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। मैं एमेज़ॉन वेब सर्विसेज़ (एडब्ल्यूएस) द्वारा भारत में अपने डेटा सेंटरों का विस्तार करने के लिए 12.7 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करता हूँ।

इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्लाउड एवं डेटा सेंटर पॉलिसी पर भी काम कर रहा है, एडब्ल्यूएस भारत में सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और स्थानीय ग्राहकों एवं साझेदारों को डिजिटल परिवर्तन लाने में मदद करने के अलावा हम 2017 से भारत में चालीस लाख से ज्यादा लोगों को क्लाउड का प्रशिक्षण दे चुके हैं, और 2025 तक अपना 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी का उद्देश्य पूरा करने के लिए छः यूटिलिटी-स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुके हैं। 2030 तक हमारा 1,05,600 करोड़ (12.7 अरब डॉलर) का योजनाबद्ध निवेश ज्यादा फायदेमंद रिपल इफेक्ट पैदा करेगा, और भारत को ग्लोबल डिजिटल पॉवरहाउस बनाने की ओर ले जाने में मदद करेगा।" उन्होंने कहा कि भारत में एडब्ल्यूएस इन्फ्रास्ट्रक्चर के निवेश से डिजिटल कौशल सहित संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव रिपल प्रभाव उत्पन्न होगा। एडब्ल्यूएस 2017 से भारत में चालीस लाख से ज्यादा लोगों को क्लाउड का प्रशिक्षण दे चुका है।

इंडिगो को मार्च तिमाही में 919.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ, परिचालन राजस्व 76 प्रतिशत बढ़ा



नयी दिल्ली, (वार्ता)। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च 2022-23 की अंतिम तिमाही में 919.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। एक साल पहले इसे इसी दौरान 1681.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

गुरुग्राम की इस कंपनी ने दिसंबर, 2022 की तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1423 करोड़ था। इस तरह चौथी तिमाही के लाभ में तिमाही दर गिरावट आयी है। कंपनी की जारी तिमाही वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार आलोच्य तिमाही में इंडिगो की परिचालन आय सालाना आधार पर 76.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14160.6 करोड़ रुपये रही जो वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के 8020.7 करोड़ रुपये के परिचालन राजस्व की तुलना में 76.5 प्रतिशत अधिक है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा, "बाजार में मजबूत मांग और अपनी रणनीति पर केंद्रित हमारे काम का मिला जुला परिणाम है कि लगातार इस दूसरी तिमाही में हमने परिचालन और वित्तीय दृष्टि से सशक्त प्रदर्शन किया है।

"इंडिगो को पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में 306 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी ने कहा है कि विनिमय दर के कारण हुई हानि को हटा दिया जाए तो वर्ष के दौरान उसे 2654 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 6162 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। आलोच्य तिमाही में कंपनी को यात्री टिकट से 12435 करोड़ रुपये की आय हुई जो सालाना आधार पर 81 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान अन्य सहायक स्रोतों से आय 37 प्रतिशत बढ़ कर 1445 करोड़ रुपये रही।

मार्च 2023 में समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी कुल खर्च चौथी तिमाही में एयरलाइन का कुल खर्च 38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13680 करोड़ रुपये रहा इस दौरान ईंधन की लागत औसतन 23 प्रतिशत ऊंची रही और इससे प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर लागत 17 प्रतिशत बढ़ कर 1.85 रुपये हो गयी। पर क्षमता का दोहन अच्छा होने से ईंधन को हटा कर प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर लागत 21 प्रतिशत घट कर 2.53 रुपये पर आ गयी।



अकासा एयर ने कोलकाता से शुरू की उड़ान

कोलकाता (वार्ता)। नई एयरलाइन अकासा एयर ने पूर्वी भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए अपने तेजी से बढ़ते नेटवर्क में 17 वें गंतव्य के रूप में कोलकाता को शामिल किया है। इस सेवा की आज पहली उड़ान शाम 17.55 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना हुयी। दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानों के साथ अकासा एयर कोलकाता को बेंगलुरु और गुवाहाटी से जोड़ेगा। यात्रियों के पास कोलकाता के माध्यम से दैनिक रूप से बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा करने का अतिरिक्त विकल्प भी होगा। इसके लिए यात्रियों को विमान बदलने बिना ही एक सहज कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। कोलकाता से शुरू हो रही विमान सेवा पश्चिम बंगाल में अकासा एयर का बागडोगरा के बाद दूसरा गंतव्य है। इसके लॉन्च के साथ शहर से इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। अकासा एयर के सह संस्थापक और चीफ कर्मशियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने कहा, "हम पश्चिम बंगाल में अपने दूसरे गंतव्य, कोलकाता से परिचालन शुरू करके बेहद खुश हैं। एक प्रमुख वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, शहर जीवन के सभी क्षेत्रों से यात्रियों को आकर्षित करता है और यह क्षेत्र कई डेस्टिनेशन का प्रवेश द्वार भी है।

मार्च में समग्र खनिज उत्पादन में 6.8 प्रतिशत वृद्धि

नयी दिल्ली, (वार्ता)। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100) के आधार आकलन में इस वर्ष मार्च में खनिजों के उत्पादन में सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत की वृद्धि रही। मार्च में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 12.5 प्रतिशत ऊंचा रहा। जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में खनिज उत्पादन सूचकांक 154.2 रहा जो मार्च, 2022 की तुलना में 6.8 प्रतिशत ऊंचा है। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के आंकड़ों के अनुसार पूरे वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च, 2022-23 की अवधि में खनिज उत्पादन में संचयी वृद्धि इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

मार्च, 2023 में कोयला 1078 लाख टन, लिग्नाइट 46 लाख टन, प्राकृतिक गैस (उपयोग में आयी) 289 करोड़ घन मीटर, खनिज पेट्रोलियम 25 लाख टन, बॉक्साइट 2115 हजार टन, क्रोमाइट 555 हजार टन, कॉपर कंसन्ट्रेट 12 हजार



टन, सोना 161 किग्रा, लौह अयस्क 281 लाख टन, लेड कंसन्ट्रेट 42 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 311 हजार टन, जिंक कंसन्ट्रेट 181 हजार टन, लाइमस्टोन 402 लाख टन, फास्फोराइट 220 हजार टन, मैग्नेसाइट 11 हजार टन और हीरे का उत्पादन तीन कैरेट रहा। कॉपर कंसन्ट्रेट का उत्पादन पिछले साल मार्च की तुलना

में 41.9 प्र.श., क्रोमाइट 34 प्र.श., फॉस्फोराइट 32.8 प्र.श., मैंगनीज अयस्क 13.6 प्र.श., कोयला 12.5 प्र.श., चूना पत्थर 7.6 प्र.श., सीसा सांद्र 6.3 प्र.श., लौह अयस्क 4.7 प्र.श., बॉक्साइट 3.6 प्र.श., और उपयोग योग्य प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.7 प्र.श. ऊंचा रहा।



ढाका में बेटियों का डंका, कनिष्ठ महिला चैंपियनशिप में स्वर्ण पर कब्जा IHF ट्रॉफी यूथ में जीता रजत पदक



बिलासपुर। ढाका में हुई आईएचएफ ट्रॉफी यूथ व कनिष्ठ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत की दोनों महिला टीमों ने स्वर्ण व रजत पदक जीता है। ढाका में 13 से 17 मई तक हुई चैंपियनशिप में भारत की यूथ व कनिष्ठ महिला टीम ने देश का प्रतिनिधित्व किया। भारत की इन दोनों टीमों में हिमाचल के बिलासपुर के मोरसिंधी में चल रही मोरसिंधी हैंडबॉल नर्सरी की 5-5 खिलाड़ियों के जोरदार खेल प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण व रजत पदक जीता। मोरसिंधी हैंडबॉल नर्सरी की संचालिका स्नेहलता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोरसिंधी हैंडबॉल नर्सरी की तेजतरंग खिलाड़ी गुलशन शर्मा की कप्तानी में भारतीय कनिष्ठ महिला हैंडबॉल टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, यूथ भारतीय महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया।

भारतीय यूथ महिला हैंडबॉल टीम में मोरसिंधी हैंडबॉल नर्सरी की कनिका, काजल, स्वाति, खुशी व प्रिया व भारतीय कनिष्ठ महिला हैंडबॉल टीम में चेतना, कृतिका, संजना, गुलशन व बबीता ने शानदार प्रदर्शन किया। मोरसिंधी हैंडबॉल नर्सरी की तेजतरंग गोलकीपर चेतना शर्मा को चैंपियनशिप में जूनियर टीम में सर्वश्रेष्ठ वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया। खिलाड़ियों का मोरसिंधी हैंडबॉल नर्सरी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। भारतीय महिला यूथ व कनिष्ठ हैंडबॉल टीम के स्वर्ण व रजत पदक जीतने पर डाक्टर आनंदेश्वर पांडे, हैंडबॉल एशोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जगनमोहन राव, महासचिव तेजराज सिंह, कोषाध्यक्ष विनय सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों व हैंडबॉल के वरिष्ठ

खिलाड़ियों ने बधाई दी है।
बास्केटबाल में ऊना, कबड्डी में सोलन चैंपियन
आईटीआई बिलासपुर में पुरुष वर्ग की आयोजित चार दिवसीय खेलों का समापन हो गया। समापन मौके पर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंवर ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता, उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बास्केटबाल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ऊना ने हमीरपुर को 41-37 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। कबड्डी के फाइनल मैच में सोलन ने शिमला को 24-33 से हराया। आईटीआई बिलासपुर के प्रधानाचार्य सुनील पटियाल ने बताया कि चार दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 413 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

कोहली ने शतक से लूटी महफिल, आरसीबी आठ विकेट से जीती



हैदराबाद, (वार्ता)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने विराट कोहली (63 गेंदें, 100 रन) के शानदार शतक और फाफ डु प्लेसिस (71) के अर्द्धशतक की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद पर आठ विकेट की दमदार जीत के साथ आईपीएल प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ा लिया।
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी सनराइजर्स ने हेनरिक क्लासेन (51 गेंद, 104 रन) के शानदार शतक की मदद से आरसीबी के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा। आरसीबी ने यह लक्ष्य चार गेंदें रहते हुए हासिल कर लिया। सनराइजर्स की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुए क्लासेन ने हैदराबाद पर अपनी छाप छोड़ते हुए 51 गेंद पर आठ चौकों और छह छक्कों की सहायता से 104 रन बनाये, हालांकि

कोहली के सैकड़े के आगे उनका प्रयास बेकार चला गया। कोहली ने आईपीएल में अपना छठा शतक बनाते हुए 63 गेंद पर 12 चौके और चार छक्के लगाकर 100 रन बनाये।
उन्होंने आईपीएल में सर्वाधिक शतक जड़ने के मामले में क्रिस गेल की बराबरी भी कर ली। कोहली और डु प्लेसिस 172 रन की साझेदारी के बाद लक्ष्य से कुछ दूर पहले आउट हो गये, जिसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने विजयी रन जड़कर आरसीबी को बहुमूल्य दो अंक दिलाये। आरसीबी इस जीत के बाद 14 अंक अर्जित करके अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गयी है, जबकि सनराइजर्स 13 मैचों में सिर्फ आठ अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है।

अंतरराष्ट्रीय

मई के अंत में चीन का दौरा करेंगे आईईए प्रमुख ग्रॉसी



बीजिंग, (वार्ता)। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी मई के अंत में चीन का दौरा करेंगे। ग्रॉसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य और वैश्विक शक्तियों में से एक के रूप में एक ऐसा देश है जिसका वक्तव्य ऐसी कई चीजों में महत्वपूर्ण है, जिनमें आईईए की भी कुछ भूमिका होती है ... जब हम वैश्विक अप्रसार संबंधी मुद्दों के बारे में बात

करते हैं, बीजिंग के साथ मेरी चर्चा अपरिहार्य हो जाती है।" उन्होंने कहा कि चीन की उनकी यात्रा 'बहुप्रतीक्षित यात्रा' है, क्योंकि चीन आईईए के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है और हर मामले, विशेष रूप से परमाणु मामलों में वैश्विक नेता है।" ग्रॉसी ने कहा कि वह यात्रा के दौरान चीन के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्रों का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि यह 2019 में आईईए के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से श्री ग्रॉसी की चीन की पहली यात्रा होगी।

इटली में बाढ़ से 13 लोगों की मौत

रोम, (वार्ता) इटली के एमिलिया-रोमाग्ना क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है तथा कई लोग अब भी लापता हैं। इन क्षेत्रों में हालांकि गुरुवार को मूसलाधार बारिश में कमी आयी, लेकिन अधिकांश क्षेत्र जलमग्न है।
स्थानीय मीडिया में गुरुवार को दिखाए गए वीडियो फुटेज में संत



अगाता सुल सैंटो कम्प्यून में सड़कों को और समुद्र तटीय शहर रेवेन्ना के कुछ हिस्से बाढ़ की पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। इटली के उत्तर-मध्य क्षेत्र (जिसमें बोलोग्ना और मोडेना शहर शामिल हैं) में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश हुयी, जिससे इन क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गयी। बचाव कर्मियों ने ऊंची इमारतों की छतों और ऊपरी मंजिल से लोगों को निकालने में मदद की।

नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार भी एमिलिया-रोमाग्ना का अधिकांश हिस्सा 'रेड अलर्ट' जोन में रहा। वहीं, उत्तर में लोम्बार्डी से लेकर दक्षिण में बेसिलिकाटा तक 'ऑरेंज' या 'येलो अलर्ट' घोषित है। उत्तर-मध्य इटली के अधिकांश हिस्सों में शनिवार आधी रात तक गंभीर मौसम की चेतावनी जारी है। विभाग ने गुरुवार अपराह्न में कहा कि 280 से अधिक

भूस्खलन की सूचना मिली है, 200 सड़कें बंद हो गई हैं और 23 नदियां उफान पर हैं। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार 10,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। वहीं हजारों लोग बिना बिजली के हैं। एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 700 तकनीशियनों को क्षेत्र में बिजली बहाल करने में मदद करने के लिए भेजा गया है। एएनएसए समाचार एजेंसी के अनुसार पर्यावरण एवं ऊर्जा सुरक्षा मंत्री गिल्बर्टो पिचेटो फ्रेटिन ने गुरुवार को कहा कि सरकार यूरोपीय आयोग को इस क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करने के लिए यूरोपीय संघ एकजुटता कोष से राशि प्रदान करने के लिए कहेगी।

ईरान ने जी7 की आर्थिक आरोपों के लिए निंदा की

तेहरान, (वार्ता)। ईरान ने ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) के वित्त मंत्रियों की ओर से ईरान पर 'अवैध वित्तीय जोखिम' का आरोप लगाने की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में जी7 की टिप्पणी को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जी7 के वित्त मंत्रियों की 'निराधार' रूप से ईरान पर 'अवैध वित्तीय जोखिम' का आरोप लगाने की कड़ी निंदा करता हूँ। गौरतलब है कि जी7 के वित्त मंत्रियों ने 13 मई को संयुक्त बयान में कहा था, "हम ईरान से निकलने वाले अवैध वित्तपोषण जोखिम से बहुत चिंतित हैं।" कनानी ने कहा, हम जी7 वित्त मंत्रियों की ओर से ईरान के खिलाफ निराधार और भ्रामक आरोप लगाए जाने की निंदा करते हैं। उन्होंने जी7 और उसके सदस्यों से अमेरिका के 'अवैध' प्रतिबंधों के 'अपमानजनक' अनुपालन को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून और ईरानी लोगों के मानवाधिकारों के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

उत्तराखण्ड प्रहरी छोटी खबरें

मान ने अवैध कब्जा करने वालों से कब्जा छोड़ने की अपील की

चंडीगढ़, (वार्ता)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंचायती, शामलात, वन विभाग या अन्य किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों से कब्जा छोड़ने की अपील की है। मान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "पंजाब में पंचायती, शामलात, वन विभाग या अन्य किसी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों से अपील है कि 31 मई तक अपना कब्जा छोड़ दें.. क्योंकि एक जून से सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। शुरू होगा अवैध कब्जों से छुटकारा अभियान..।"

घर में मैस घुसने के विवाद में चाचा की लाटियों से पीट पीटकर हत्या

शिवपुरी, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की उसके भतीजे ने अपने माता पिता के साथ मिलकर लाटियों से पीट पीटकर हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 17 मई को उमेद रावत एवं परिवार के अन्य सदस्य अपने घर के आंगन में दाल साफ कर रहे थे। तभी उसके बड़े भाई त्रिलोक रावत की भैंस उनके घर में घुस आई और दाल खराब करने लगी, जिसे भगा दिया। इसके बाद त्रिलोक रावत उनका पुत्र सत्येंद्र रावत, गुड्डू बाई, कामिनी रावत एवं हाकिम रावत ने उनके घर में घुसकर लाटियों से हमला कर दिया जिसमें सभी को चोटें आईं एवं उमेद गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ग्वालियर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने ग्वालियर जाकर कार्रवाई शुरू की तथा सत्येंद्र एवं गुड्डू बाई को गिरफ्तार कर लिया है। शेष तीन आरोपियों की तलाश की जा रही है।

अनियमितता के आरोप में तीन पटवारी निलंबित

रायसेन, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में प्राकृतिक आपदाओं के तहत वित्तीय सहायता राशि के आहरण में अनियमितता के आरोप में तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने अनुयाग राजपूत तत्कालीन पटवारी तहसील बेगमगंज, सुल्तानपुर तहसील के हल्का नम्बर-29 के पटवारी एवं क्रियेटर आईडी धारक शैलेश सिंह राजपूत और सुल्तानपुर तहसील के पटवारी सचिन मुजालदा को निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि जिले में प्राकृतिक आपदाओं के तहत वित्तीय सहायता राशि के आहरण मामले में अनियमितता की गयी है।

विधायक के लेटर पैड पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में शिकायत दर्ज

दमोह, (वार्ता)। मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पथरिया विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की विधायक रामबाई सिंह परिहार के लेटर पैड का कथित तौर पर दुरुपयोग कर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में शिकायत दर्ज करायी गयी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विधायक रामबाई ने कल इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी राकेश कुमार सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करायी है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि किसी जनप्रतिनिधि के लेटर पैड का किसी तरह से दुरुपयोग करना कानूनन अपराध है। मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जो भी व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गुलामी के समय धरोहरें नष्ट होने से दुनिया का नुकसान, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो-2023 के शुभारंभ पर बोले मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में जहां कितनी ही पांडुलिपियां और पुस्तकालय जला दिए गए, वहीं आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे, वह भी नहीं किए गए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही। बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (आईएमडी) का जश्न मनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के सैकड़ों सालों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान यह भी किया कि हमारी लिखित और अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। हमारी कितनी ही पांडुलिपियां और पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए। यह केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया और पूरी मानवजाति का नुकसान था।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने



के जो प्रयास होने चाहिए थे, वह हो नहीं पाए। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है और उनमें प्रमुख है 'अपनी विरासत पर गर्व'। बता दें कि इस साल के लिए अंतरराष्ट्रीय

संग्रहालय दिवस का विषय 'संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण' है। लकड़ी से बनी डॉसिंग गर्ल-वचुअल वॉकथ्रू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लकड़ी से बनी डॉसिंग गर्ल और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने वाले नेशनल म्यूजियम के एक वचुअल वॉकथ्रू का उद्घाटन किया। इसके

साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्राफिक नॉवेल – संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कलात्मक पथ के पोकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो प्रदर्शनी का निरीक्षण करते वीडियो भी सामने आया है।

ममता के भतीजे पर 25 लाख का जुर्माना, कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक की अर्जी खारिज की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिक्षक भर्ती घोटाले में सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दे



दी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पहले के आदेश में अदालत ने स्कूल भर्ती मामले में ममता बनर्जी के भतीजे से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी को अनुमति दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने अदालत कक्ष में आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ा। पीठ ने टीएमसी के गिरफ्तार युवा नेता कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी की अर्जियों को खारिज कर दिया है।

दी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पहले के आदेश में अदालत ने स्कूल भर्ती मामले में ममता बनर्जी के भतीजे से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी को अनुमति दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने अदालत कक्ष में आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ा। पीठ ने टीएमसी के गिरफ्तार युवा नेता कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी की अर्जियों को खारिज कर दिया है।

बम बनाने की इकाई बन गया बंगाल : सुकांत



कोलकाता (वार्ता)। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया राज्य को बम बनाने की इकाई बना दिया गया है। मजूमदार ने कहा, "पश्चिम बंगाल को बम बनाने वाली इकाई में बदल दिया गया है। एगरा में भयानक बम विस्फोट के खिलाफ भगवानपुर में एक विरोध रैली में भाग ले रहे हमारे कार्यकर्ताओं पर बम फेंके गए। प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता

टीएमसी के गुंडों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। बल्कि उनका विरोध करें और उन्हें बाहर करें।" यहां यह उल्लेखनीय है कि मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था जिसमें पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में बड़े पैमाने पर हुये विस्फोट के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एनआईए द्वारा जांच की मांग की गई थी। इस घटना में नौ लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।

वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर शुरू होगी वंदे मेट्रो : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

पुरी-हावड़ा (वार्ता)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देशभर में रेल यात्रियों को वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो रही है और अब इसी तर्ज पर नगरों तथा महानगरों के आसपास के लोगों को अगले साल मार्च से 'वंदे मेट्रो' सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वैष्णव ने पुरी से हावड़ा के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगरों और महानगरों में 100 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए वंदे मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वंदे मेट्रो सेवा देने के लिए लगातार काम चल रहा है और अगले साल मार्च तक यह सुविधा आरंभ कर दी जाएगी। वंदे भारत रेलों



के नेटवर्क के बारे में पूछे जाने पर रेलमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की देशभर में जबरदस्त मांग है और

से हर रूट पर 30 से 40 प्रतिशत समय की बचत हो सकेगी।

कांग्रेसियों ने ज्ञापन भेजकर की भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल भूपतवाला क्षेत्र में प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने एक बेशकीमती जमीन पर की गई तार बाढ़ और टीन शेड को मेयर अनीता शर्मा, मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा और कांग्रेसी पार्षदों ने पिछले दिनों अवैध कब्जा बताते हुए मौके पर जाकर हटा दिया था। उसके बाद बीजेपी पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर उक्त जमीन को नगर निगम की बोर्ड बैठक में पास करा कर प्रेम प्रकाश आश्रम को दिए जाने की बात कही थी।

शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को



ज्ञापन भेजा है, ज्ञापन में कहा है कि प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने बेशकीमती जमीन है जिसे पिछले दिनों समाजसेवियों ने मिलकर कब्जामुक्त कराया था, अब फिर से भू-माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया

है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से जांच कराकर भू-माफिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने में दिनेश पुंडीर, मनोज जाटव, बृजमोहन, नावेद अंसारी और वसीम सलमानी मौजूद रहे।



अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन का गठजोड़

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

भगवानपुर(हरिद्वार)। हरिद्वार पुलिस व प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण क्षेत्र माहडी चौक पर सरकारी भूमि से 19 मई शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत चौक स्थित सरकारी जमीन पर बनाई गई 10 स्थायी दुकानों को हटाया गया। अन्य स्थानों पर चिन्हीकरण की कार्यवाही भी जारी है।

संयुक्त
रूप से भगवानपुर
क्षेत्र में हटाया गया
अतिक्रमण



भारत में बदलाव मेरी जीवन भर की महत्वाकांक्षा: केसीआर

नांदेड़ (महाराष्ट्र), (वार्ता)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने शुक्रवार को कहा कि उनकी आजीवन महत्वाकांक्षा भारत में बदलाव लाने की है।

तेलंगाना की सीमा नांदेड़ में बीआरएस पार्टी प्रशिक्षण शिविर कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि बदलाव की शुरुआत महाराष्ट्र से होगी और देश में बदलाव बीआरएस पार्टी का अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन ने देश की राजनीति को बदल दिया और आंदोलन के दौरान सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और मधु धंडावते और अन्य वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि धार्मिक द्वेष, शराब और वोट के पैसे बांटने का चलन है, हमारा लक्ष्य नहीं भटकना चाहिए।



दहेज मांगने और मारपीट का आरोपी था चुपके से विदेश भागने की तैयारी कर रहा था

उत्तराखण्ड प्रहरी ब्यूरो

लक्सर, (हरिद्वार)। ग्राम लक्सर निवासी युवती की शिकायत पर कोतवाली लक्सर में दहेज अधिनियम एवं मारपीट आदि के सम्बन्ध में दिनांक 18.04.2023 को दर्ज मु0अ0सं0 343/23 की विवेचना कर रही महिला उपनिरीक्षक को जानकारी मिली कि आरोपी दानिश निवासी धनपुरा पथरी अपने आप को छिपाते हुए विदेश भागने की तैयारी कर रहा है। साथ ही आरोपी युवक द्वारा विवेचना में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया।

उक्त सम्बन्ध में विवेचक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय

से अभियुक्त दानिश का वारंट प्राप्त किए। आरोपी की तलाश हेतु लगातार प्रयास करते हुए आज दिनांक 19-05-2023 को मुखबिर की सूचना पर दानिश उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण

▶ दानिश पुत्र अमरेज निवासी धनपुरा पथरी

पुलिस टीम

▶ उ0नि0 एकता मंगगाई
▶ हे0का0 हमीद खान

विश्व मधुमक्खी दिवस

20 मई को मध्य प्रदेश में

नयी दिल्ली, (वार्ता)। कृषि मंत्रालय की ओर से 20 मई को राजा भोज कृषि महाविद्यालय, बालाघाट, मध्यप्रदेश में विश्वमधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्यप्रदेश सरकार के कृषिमंत्री तथा कई अन्य विशिष्ट लोग इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 किसानों और शहद उत्पादन से जुड़े सभी हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है।

विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह के दौरान, मधुमक्खी पालन क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों, प्रोसेसरों और विभिन्न हितधारकों द्वारा मधुमक्खी पालन क्षेत्र में मधुमक्खी की विविध किस्मों और विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 100 से अधिक स्टालों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तकनीकी सत्रों के आयोजन में उत्पादन, अनुसंधान, उद्योगों के साथ साझेदारी, घरेलू और निर्यात के लिए बाजार रणनीति और रविपणन चुनौतियां तथा स मा धा न (घरेलू/वैश्विक) एवं परिचर शामिल है। भारत की विविध कृषि-

जलवायु परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन/शहद उत्पादन के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए और अन्य मधुमक्खी उत्पादों जैसे; मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और मधुमक्खी वेनोम के उत्पादन को बढ़ावा देकर शहद के उत्पादन और परीक्षण को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा रही है। मधुमक्खियां स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले आहार और अन्य उत्पादों को प्रदान करने में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मधुमक्खियों का काम इससे कहीं अधिक है।

